4 बेबाकी से अपना पक्ष रखती हैं महुआ मोइत्रा

6 मुख्यमंत्री साय ने किया विवरणिका का विमोचन

7 सीएम साय ने सपरिवार किया बाबा महाकाल के दर्शन

RNI-MPBIL/2011/39805

निष्पक्ष और निर्भीक साप्ताहिक

जगत प्रवाह

वर्ष : 15 अंक : 15 प्रति सोमवार, 19 अगस्त 2024 मूल्य : दो रुपये पृष्ठ : 8

मध्यप्रदेश में मंत्रियों को मिले जिलों के प्रभार में अनुभव और वरिष्ठता को नहीं दी तवज्जो

प्रदेश के दो बड़े नेताओं को मिला कमजोर जिलों का प्रभार

मुख्यमंत्री का यह निर्णय जनता के हित और विकास में होगा बाधक

कवर स्टोरी

-विजया पाठक

एडिटर

हाल ही में मध्यप्रदेश की डॉ. मोहन यादव सरकार ने अपने मंत्रियों को जिलों का प्रभार सौंपा है। प्रभार में लगभग सभी जिलों को कवर किया गया है। प्रभारी जिलों की सूची देखने पर लग रहा है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने अपने सहयोगियों की वरिष्ठता और अनुभव को दरकिनार किया है। प्रदेश के दो वरिष्ठ मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और प्रहलाद पटेल जैसे दिग्गज मंत्रियों को छोटे जिलों का प्रभार दिया है जबकि उनका अनुभव

और काबिलियत को देखते हुए अन्य बड़े जिलों का प्रभार भी सौंपा जा सकता था। निश्चित ही यदि इन्हें बड़े जिलों का प्रभार मिलता तो विकास की जो रफ्तार चल रही है उसको और अधिक गति मिलती। लेकिन प्रदेश के मुखिया ने विकास को छोड़ खुद का प्रबंधन मजबूत किया। इस सूची को देखने के बाद राजनीतिक विशेषज्ञ मुख्यमंत्री के निर्णय पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। निश्चित ही मुख्यमंत्री का यह निर्णय विचारणीय है। आपको बता दें कि स्वतंत्रता दिवस के दो दिन पूर्व ही मोहन यादव ने अपनी सुविधानुसार अपने लोगों को लाभ दिलवाने के उद्देश्य से जिलों का प्रभार सौंपा है। जबकि पार्टी के वरिष्ठ नेता व मंत्रियों को एक बार फिर हाशिये पर रखा गया है। (शेष पेज 2 पर)

छत्तीसगढ़ में साय सरकार का 180 दिनों का कार्यकाल जनकल्याण के लिये रहा समर्पित

महिला, किसान, बेटियों, युवाओं सहित हर वर्ग के लोगों को मुख्यमंत्री ने दी सौगात

-विजया पाठक

छत्तीसगढ़ में भाजपा की विष्णुदेव साय सरकार ने अपने कार्यकाल का 06 महीना पूरा कर लिया है। सरकार अपनी योजनाओं को लगागार जमीनी रूप देने में जुटी हुई है। जिसके चलते लगातार छत्तीसगढ़ विकास के पैमाने पर आगे बढ़ रहा है। इसलिए छत्तीसगढ़ सरकार पिछले 06 माह के काम को अपनी बड़ी उपलब्धि मान रही है। राज्य में अपनी सरकार के 180 दिन पूरे होने के अवसर पर प्रसन्नता जाहिर करते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ में साय सरकार ने पहले 6 माह में अपने किए वादों को पूरा करने की कोशिश की है। कुछ वादों को पूरा किया गया है, कुछ बादे अभी बाकी रह गए हैं। अब देखना होगा कि आगे साय सरकार क्या इसी रफ्तार से योजनाओं को पूरा करेगी या नहीं। हालांकि, लोकसभा चुनाव में मिली जीत से यह साफ है कि साय सरकार के कामों पर जनता ने जरूर मुहर लगा दिया है। (शेष पेज 2 पर)

मुख्यमंत्री साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ ने प्रधानमंत्री मोदी के एक पेड़ मां के नाम के संकल्प को किया पूरा

-विजया पाठक

देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करोड़ों देशवासियों से आह्वान किया है कि आइए माँ के नाम एक पेड़ लगाइए। इस पहल का मुख्य उद्देश्य पर्यावरण को सुधारना और धरती माँ को हरियाली से सजाना है। भारत भूमि पर पेड़-पौधों का महत्व हमारे धर्मग्रंथों में व्यापक रूप से वर्णित है। जिस तरह अलग-अलग अंचलों में विभिन्न बोली-भाषाओं का चलन है, उसी प्रकार यहाँ विभिन्न प्रकार के पेड़-पौधे भी पाए जाते हैं। छत्तीसगढ़ के लोकप्रिय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रदेशवासियों से अपील करते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी की इस पहल को साकार करने के लिए हर व्यक्ति माँ के नाम पर एक पौधा अवश्य लगाए। (शेष पेज 3 पर)

आजादी के 75 वर्ष बाद भी आखिर क्यों शुरू हुआ 09 अगस्त और 15 नवंबर के बीच गतिरोध?

पेज 3 पर

छत्तीसगढ़ में साय सरकार का 180 दिनों का कार्यकाल जनकल्याण के लिये रहा समर्पित

(पेज 1 का शेष)

साय सरकार ने विकास योजनाओं को दी गति

छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय सरकार बनने के बाद विकास योजनाओं को गति दी गई है। सरकार ने कृषक उन्नति से समृद्ध किसान योजना के तहत किसानों का धान 3100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से खरीदा है। 2 साल का 3716 करोड़ रुपए का बकाया बोनस किसानों को दिया गया। 18 लाख से अधिक परिवारों के लिए पीएम आवास की मंजूरी मिली। एक करोड़ से अधिक परिवारों को 5 साल के लिए खाद्य सब्सिडी दी। महतारी वंदन योजना के तहत 70 लाख महिलाओं को हर साल 12000 की मदद दे रहे। तेंदूपत्ता का मानदेय बढ़ाकर 5500 प्रति मानक बोरा किया गया। सरकारी नौकरी भर्ती पर आयु सीमा में 5 साल की छूट मिली है।

विधानसभा चुनाव के बाद और मजबूत हुई बीजेपी

छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बनने के बाद से छत्तीसगढ़ में भाजपा मजबूत हुई है। विधानसभा चुनाव में जीत के बाद विष्णुदेव साय ने बतौर मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ की बागडोर संभाली। उसके बाद से भाजपा यहां मजबूत हुई। इसका सबसे बड़ा परिणाम लोकसभा चुनाव में मिली सफलता है। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी 9 सीटों पर जीती थी, जबकि 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 10 सीटों पर जीत हासिल किया है। 2024 में बस्तर लोकसभा सीट को भी बीजेपी ने जीत लिया है। यह बीजेपी के लिए बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि 6 महीने पहले ही छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार बनी थी।

नक्सलवाद की लड़ाई निर्णायक मोड़ पर पहुंची

प्रदेश में विष्णुदेव साय की सरकार बनने के बाद नक्सलियों का सफाया करने जिस तरीके से अभियान चलाया गया, उसने पूरे देश में छत्तीसगढ़ को "नक्सली सफाई का मॉडल" बना दिया। बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हो या फिर गृहमंत्री अमित शाह, सभी लोगों ने छत्तीसगढ़ में नक्सलियों की सफाई को प्राथमिकता दी। पिछले छह महीने में सुरक्षाबलों ने 129 नक्सलियों को मारा गिराया है, जबकि 488 को गिरफ्तार किया है। वहीं पुनर्वास योजना से प्रेरित होकर 431 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण भी किया है। नक्सलवाद की लड़ाई में राज्य एक निर्णायक मुकाम तक पहुंच गई है। छत्तीसगढ़ को जल्द नक्सली मुक्त कर दिया जाएगा, इसकी गारंटी भी छत्तीसगढ़ सरकार दे रही है।

विकास के लिए आये हैं, विकास करेंगे

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा, "हम विकास करने के लिए आए हैं और हम विकास करके रहेंगे। छत्तीसगढ़ की जनता ने हमें जनमत दिया है, उनके जनमत पर हम खरा उतरेंगे। बात विधानसभा की हो या फिर लोकसभा की, दोनों चुनाव में छत्तीसगढ़ की जनता ने पूरा स्नेहा हमें दिया। "काम करने का जो मौका छत्तीसगढ़ की जनता ने भाजपा को दिया है, भाजपा उनकी उम्मीदों पर खरा उतरेंगी।

नए सीएम ने किया कमाल

लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने बंपर जीत दर्ज की है। पार्टी ने 11 में से 10 सीट जीती है। पार्टी की इस बंपर जीत पर सीएम ने प्रतिक्रिया दी है। सीएम ने कहा कि प्रदेश की जनता ने मोदी की गारंटी पर अभूतपूर्व भरोसा दिखाया है। हमें माता बहनों, किसान-मजदूरो, युवाओं सहित हर वर्ग का समर्थन मिला है। सीएम ने इसके लिए जनता का आभार व्यक्त किया है।

06 महीने में की रमन सिंह की बराबरी

प्रदेश में बीजेपी की तरफ से साल 2009 और 2014 में रमन सिंह की सरकार होने पर पार्टी को 11 में से 10 सीटें मिली थी। वहीं, 6 महीने पहले ही विधानसभा चुनाव जीतकर बीजेपी सरकार बनने के बाद सीएम बने विष्णुदेव साय ने भी लोकसभा चुनाव में कमाल करते हुए 11 में से 10 सीटें जीतने में सहयोग किया है।

सीएम ने ऐसे दिलाई जीत

सीएम विष्णुदेव साय ने सरकार की कमान संभालने के साथ ही चुनाव प्रचार के समय पीएम मोदी के किए गए वादों पर काम करना शुरू कर दिया। साथ ही उनकी गारंटी वाली योजनाओं को लागू कर दिया। इसके चलते जनता के बीच पार्टी के लिए भरोसा बना। इसके साथ ही नक्सल प्रभावित इलाकों में नक्सलवाद के खिलाफ काम करते हुए जनता के मन में सुरक्षा की भावना को पैदा किया। बीजेपी के विकास कार्यों को देखते हुए पार्टी ने उनको चुना।

आवासहीनों को उपलब्ध करवाये आवास

साय सरकार ने आवासहीन और जरूरतमंद 18 लाख परिवारों के लिए प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति, 13 लाख से अधिक किसानों को धान की बोनस राशि, 3100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से और 21 क्विंटल प्रति एकड़ के मान से धान खरीदी, महतारी वंदन योजना में 70 लाख से अधिक गरीब परिवारों की महिलाओं को हर माह एक-एक हजार रूपए देने जैसे अनेक निर्णयों पर क्रियान्वयन किया है। राज्य के माओवाद प्रभावित क्षेत्रों में माओवाद उन्मूलन के लिए तेजी से काम किया जा रहा है। इन क्षेत्रों में लोगों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए नियद नेल्लानार योजना शुरू की गई है।

13 लाख किसानों को धान का बोनस

पीएम मोदी ने प्रदेश के किसानों को गारंटी दी थी कि सरकार बनने पर राज्य के किसानों को 2 साल का बकाया धान बोनस देंगे। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिवस, सुशासन दिवस पर छत्तीसगढ़ सरकार ने 13 लाख किसानों के बैंक खातों में 3716 करोड़ रुपए का बकाया धान बोनस अंतरित कर इस गारंटी को भी पूरा किया है।

तेन्दूपत्ता संग्रहण दर अब 5500 रुपए

राज्य में तेंदूपत्ता संग्रहण पारिश्रमिक दर 4000 रुपए प्रति मानक बोरा से बढ़ाकर अब 5500 रुपए प्रति मानक बोरा कर दी गई है। चालू तेंदूपत्ता सीजन से ही 12 लाख 50 हजार तेंदूपत्ता संग्राहकों को योजना का लाभ मिल रहा है। संग्राहकों के लिए राज्य सरकार द्वारा चरण पादुका योजना भी शुरू की जाएगी, साथ ही उन्हें बोनस का लाभ भी दिया जाएगा।

भर्ती में युवाओं को पांच वर्ष की छूट

युवाओं की बेहतरी के लिए राज्य सरकार ने अहम निर्णय लेते हुए पुलिस विभाग सहित विभिन्न शासकीय भर्तियों में युवाओं को निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट का निर्णय लिया है। अभ्यर्थियों को 31 दिसंबर 2028 तक आयु सीमा में 05 वर्ष छूट का लाभ मिलेगा।

यूपीएससी की तर्ज पर होगी पीएससी

यूपीएससी की तर्ज पर छत्तीसगढ़ पीएससी परीक्षा को पारदर्शी बनाने के लिए यूपीएससी के पूर्व चेयरमैन प्रदीप कुमार जोशी की अध्यक्षता में आयोग का गठन कर दिया गया है। पीएससी की घोटाले की जांच सीबीआई को सौंप दी गई है।

पांच शक्तिपीठों का होगा विकास

राज्य की 5 शक्तिपीठों के विकास के लिए बजट में 5 करोड़ रुपए का प्रावधान कर दिया गया है। शक्तिपीठों के विकास के लिए चारधाम की तर्ज पर 1000 किलोमीटर की परियोजना शुरू की जाएगी। ग्रामीण घरों को नल से जल की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए जल जीवन मिशन के अंतर्गत 4500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।

युवाओं के लिए उद्यम क्रांति योजना

राज्य में युवा स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए उद्यम क्रांति योजना शुरू करते हुए बजट प्रावधान भी कर दिया है। इस योजना के तहत युवाओं को स्वरोजगार स्थापित करने के लिए 50 प्रतिशत सब्सिडी पर ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराए जाने की व्यवस्था की गई है।

अधोसंरचना और कनेक्टीविटी पर जोर

राज्य में सड़क, रेल और हवाई यातायात की सुविधाओं के विस्तार का काम भी शुरू हो चुका है। बिलासपुर और जगदलपुर से नयी उड़ानें शुरू हो चुकी हैं। जशपुर और बलरामपुर हवाई पट्टी के विस्तार के लिए बजट में प्रावधान कर दिया गया है। अंबिकापुर और जगदलपुर हवाई अड्डों में भी सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है।

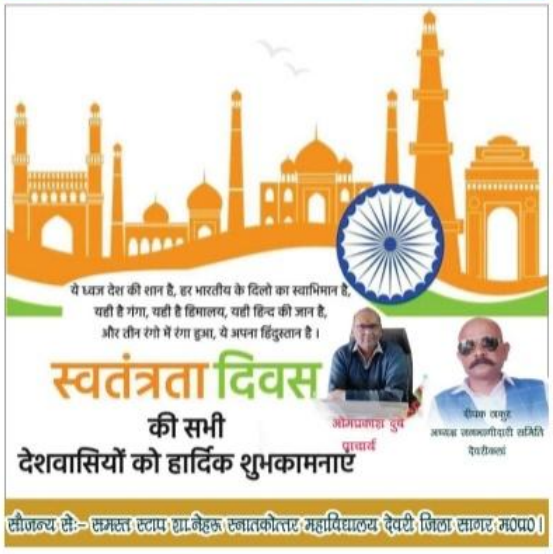

मध्यप्रदेश में मंत्रियों को मिले जिलों के प्रभार में अनुभव और वरिष्ठता को नहीं दी तवज्जो

(पेज 1 का शेष)

दो बड़े मंत्रियों के साथ हुआ भेदभाव

मंत्रालय में प्रभार के जिलों की जारी हुई सूची के बाद चर्चा है कि प्रदेश के दो बड़े मंत्रियों के साथ मोहन सरकार ने एक बार फिर छलावा किया है। दरअसल यह चर्चा नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और पंचायत मंत्री प्रहलाद पटेल को लेकर है। दोनों ही प्रदेश के बड़े नेताओं में शुमार हैं और प्रहलाद पटेल तो केंद्रीय मंत्रीमंडल के सदस्य रहे हैं।

32 मंत्री और 55 जिले

जानकारी के अनुसार मध्यप्रदेश में 55 जिले हैं और मुख्यमंत्री सहित 32 मंत्री हैं। सीएम मोहन यादव चाहते थे कि सभी 55 जिलों में प्रभारी मंत्री रहें। जानकारी के मुताबिक, मुख्यमंत्री मोहन यादव ने प्रभारी मंत्रियों की सूची तैयार कर दिल्ली से उस पर मुहर लगवाई ताकि कोई सवाल न उठाए। मोहन यादव खुद हर एक जिले और हर एक मंत्री को लेकर विचार विमर्श करते रहे कि आखिर किस मंत्री को कौनसे जिले का प्रभार देना चाहिए।

इंदौर का प्रभार स्वयं के पास रखने के पीछे क्या कोई खास मकसद?

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के पास प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर का प्रभार आया है तो उपमुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा के पास जबलपुर और देवास का प्रभार दिया गया है। डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल को सागर और शहडोल का प्रभार मिला है। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय को सतना और धार का प्रभार दिया गया है, जबकि पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल को भिंड और रीवा का प्रभार दिया गया है। यह आश्चर्यजनक है क्योंकि माना जा रहा था कि इनमें से किसी एक को छिंदवाड़ा का प्रभार दिया जाएगा। इसके बजाय पीडब्ल्यूडी मंत्री और पूर्व भाजपा प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह को छिंदवाड़ा और नर्मदापुरम का प्रभार दिया गया।

विजयवर्गीय के साथ हुई नाइंसाफी

कैलाश विजयवर्गीय ने लोकसभा चुनाव के दौरान छिंदवाड़ा में भाजपा के अभियान का नेतृत्व किया था, जब विवेक बंटी साहू ने कांग्रेस के दिग्गज नेता कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ को हराया था। प्रहलाद पटेल 2004 में छिंदवाड़ा से भाजपा के उम्मीदवार थे और 2023 के चुनावों के दौरान सात विधानसभा सीटों के प्रभारी हैं। ऐसे में इतनी उपलब्धियां होने के बाद भी मोहन यादव ने जिस ढंग से विजयवर्गीय को कमजोर जिले का प्रभार दिया वह उनके साथ हुई नाइंसाफी की ओर इशारा करता है। हम जानते हैं कि विजयवर्गीय ने पश्चिम बंगाल जैसे राज्य में भाजपा को खड़ा किया है। उनमें संगठन और शासन का काफी अनुभव है। बड़े जिलों की जिम्मेदारी देकर मुख्यमंत्री उनका सही उपयोग कर सकते थे। सीधी सी बात है मोहन बिलकुल नहीं चाहते कि उनके बराबर कोई राजनेता किसी बड़े जिले का प्रभार संभाले। इसीलिए उन्होंने प्रह्लाद पटेल और विजयवर्गीय को कमजोर जिले दिए हैं।

इन्हें मिला केवल एक जिले का प्रभार

सीएम डॉ. मोहन यादव ने वरिष्ठ मंत्रियों को दो जिलों का प्रभार दिया है। बाकी 8 मंत्रियों को केवल एक जिले का प्रभारी बनाया गया है। इनमें धर्मेंद्र सिंह लोधी को खंडवा, दिलीप जायसवाल को सीधी, गौतम टेटवाल को उज्जैन, नारायण सिंह पंवार को रायसेन, नरेंद्र शिवाजी पटेल को बैतूल, प्रतिमा बागरी को डिंडौरी, दिलीप अहिरवार को अनूपपुर और राधा सिंह को मैहर जिले का प्रभारी बनाया गया है।

आजादी के 75 वर्ष बाद भी आखिर क्यों शुरू हुआ 09 अगस्त और 15 नवंबर के बीच गतिरोध

क्या देश के राजनेताओं ने जनजातीय समाज के सम्मान के साथ राजनीति करना आरंभ कर दिया है?

-विजया पाठक

जनजातीय आबादी के मान से भारत विश्व का प्रमुख देश है। यहां विभिन्न राज्यों में एक नहीं बल्कि विभिन्न जनजातीयों के लोग निवास करते हैं। खास बात यह है कि यह लोग आज भी अपने पारंपरिक संस्कृति को जीवंत रखने का प्रयास कर रहे हैं। इन जनजातीयों के इसी जज्बे को देखते हुए 09 अगस्त 1994 में अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी दिवस की स्थापना की गई। तब से लेकर लगातार 25 वर्षों से अधिक समय तक यह दिवस पूरे विश्व में गरिमामय ढंग से आयोजित किया जाता रहा है। लेकिन पिछले कुछ समय से यह देखने में आया है कि राजनैतिक द्वेष के कारण अब राजनीति ने जनजातीयों के सम्मान के लिये आयोजित किये जाने वाले इस दिन को भी अखाड़े का मैदान बना दिया है। जबकि देखा जाये तो जनजातीय समाज की अपनी नैसर्गिक विरासत है, जिसमें निश्छल जीवन का संघर्ष प्रतिबिंबित हैं। जनजातीय जीवन-शैली में आलोकित आनंद समूचे देश की ऊर्जा और उसका दैनंदिन संघर्ष का प्रतिबिंब है।

कब तक तारीख के पीछे सम्मान देने से चूकेंगे

जनजातीय समाज के सम्मान की बात जहां आती है तो हम सभी का कर्तव्य बनता है कि हम उस समाज की रक्षा के लिये चिंता करें और उसकी समृद्धि के लिये निरंतर कार्य करें। लेकिन आज देश में जनजातीय लोगों के नाम पर जबरदस्त राजनीति छिड़ी हुई है। आखिर कब तक हम 09 अगस्त और 15 नवंबर की तारीखों के बीच में जनजातीय समाज की प्रतिष्ठा और उसके सम्मान के साथ खिलवाड़ करेंगे। आखिर क्यों नहीं हम विश्व स्तर पर घोषित किये गये अंर्तराष्ट्रीय जनजातीय दिवस को स्वीकार कर 09 अगस्त को ही उनके सम्मान का दिवस मनाने का प्रयास करते हैं। यह गहन चिंता का विषय है कि जिसे आगामी समय में देश के नेताओं और प्रधानमंत्री को मंथन करना चाहिए।

15 नवंबर से आपत्ति नहीं लेकिन 09 अगस्त से क्यों?

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी व उनकी सरकार लगातार जनजातीय समाज के संरक्षण व संवर्धन की बात करते हैं। लगातार उनके विकास की कार्ययोजनाओं को तैयार करते हैं और उनका लाभ जनता तक पहुंचाने का काम भी कर रहे हैं। लेकिन फिर प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सरकार को 09 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी दिवस मनाने का परहेज क्यों है। कहीं इस परहेज की एक वजह यह तो नहीं कि तीन वर्ष पहले प्रधानमंत्री मोदी ने खुद 15 नवंबर को मध्यप्रदेश की धरती से भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की इसलिये वे खुद इस दिवस पर फोकस रहकर काम करते हैं। अगर ऐसा है तो यह चिंता का विषय है और इस तरह के गतिरोध को तत्काल प्रभाव से समाप्त करने की आवश्यकता है।

दुनिया के 70 देशों में आदिवासियों का प्रभाव

दुनिया में करीब 200 देश हैं, जिनमें से 70 देशों में आदिवासियों का प्रभाव दिखता है। दुनिया में 5000 आदिवासी समाज की 7000 भाषाएं हैं। दिसंबर 1994 में संयुक्त राष्ट्र ने यह निर्णय लिया था कि विश्व के आदिवासी लोगों का अंतरराष्ट्रीय दिवस हर साल 09 अगस्त के दिन मनाया जाएगा। यह दिन आदिवासियों की संस्कृति, सभ्यता, उपलब्धियों और समाज और पर्यावरण में उनके योगदान की तारीफ करने का दिन होता है।

भारत में आदिवासियों की स्थिति

साल 2011 की जनगणना के मुताबिक, देश में फिलहाल अनुसूचित जनजातियों की आबादी 10.45 करोड़ हो चुकी है। ये कुल आबादी का 8.6 फीसदी है। भारत में करीब 705 जनजातीय समूह हैं। इनमें 75 विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह हैं।

इन राज्यों में आदिवासियों की आबादी

भारत में आदिवासी मुख्य रूप से ओडिशा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखण्ड, अंडमान-निकोबार, सिक्किम, त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड और असम में काफी बड़ी संख्या में पाए जाते हैं। इनमें सबसे खास अंडमान द्वीप पर स्थित सेंटीनल में रहने वाली जारवा नामकी जनजाति है, जिन्हें दुनिया का सबसे पुराना जीवित आदिवासी समाज माना जाता है। अंडमान द्वीप पर स्थित सेंटीनल में जारवा जनजाति आज मुश्किल से 400 के करीब बचे हैं. ये सुअर, कछुआ और मछली खाकर जीवित रहते हैं। इनके साथ फल जड़ीवाली सब्जियां और शहद भी इनके खाने में शामिल हैं।

कई मौलिक सुविधाओं से वंचित

शहरों की चमक दमक से दूर प्रकृति के छांव में रहने वाले आदिवासी कई मौलिक सुविधाओं से वंचित हैं। विकास की दौड़ में वो पीछे ना रह जाएं, इसके लिए संविधान के निर्माण के वक्त ही इनके लिए सरकारी नौकरियों में 7.5 फीसदी आरक्षण की व्यवस्था की गई। अभी उसमें भी क्रीमी लेयर लाने की बात सुप्रीम कोर्ट ने कही, तो विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर उनका ये सवाल सतह पर आ चुका है।

10 करोड़ से अधिक हैं आदिवासी

भारत में करीब साढ़े 10 करोड़ आदिवासी हैं। इनकी सादगी, इनका विश्वास, इनके मूल्य...ये सब मिलकर भारत ही नहीं, बल्कि दुनिया के सामने एक ऐसा समाज बनाते हैं जिनकी आस्था में प्रकृति बसती है। अगर दुनिया का फेफड़ा जिंदा है, अगर लोगों को सांस लेने के लिए थोड़ी बहुत साफ हवा मिल जाती है, तो इन लोगों की बदौलत है। इन लोगों के लिए प्रकृति से प्रेम ही ईश्वर के प्रति प्रेम है। अंतरराष्ट्रीय आदिवासी दिवस पर जब भारत समूची दुनिया के आदिवासियों के संकल्प और संताप में एक साथ शामिल होता है, तो उसके सामने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू एक नया मिसाल पेश करती है।

कौन होते हैं आदिवासी?

आदिवासी उन्हें कहते हैं, जो प्रकृति की पूजा करने और उसकी रक्षा करने वाले हैं। जिन्हें जंगल, पेड़, पौधों और पशुओं से बेहद प्यार है। उनकी जीवन शैली सादा है, स्वभाव शालीन और शर्मीला होता है। ये पारंपरिक भोजन करते हैं। अपने त्योहारों को वैभव से नहीं, बल्कि विश्वास से उल्लास में बदलते हैं। आदिवासी शिकार में माहिर होते हैं। धनुष-बाण उनके हथियार होते हैं। वो अपने पूर्वजों की बनाई परंपरा का सच्चे दिल से पालन करते हैं। उन्हें अपनी परंपरा से निकली कला और गीत-संगीत से बेहद लगाव होता है। उन्हें अपनी भाषा, संस्कृति और मिट्टी से स्वाभाविक अनुराग होता है। वो जड़ी-बूटियों और औषधियों का बहुत बारीक ज्ञान रखते हैं।

पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने की थी 09 अगस्त को अवकाश की मांग

पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को मध्यप्रदेश में 09 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस पर अवकाश की मांग को लेकर पत्र लिखा था। उन्होंने अपने पत्र में लिखा है कि 'संयुक्त राष्ट्र संघ के आह्वान पर सम्पूर्ण विश्व दिनांक 09 अगस्त को "विश्व आदिवासी दिवस" के रूप में मनाता है। लेकिन मध्यप्रदेश सरकार द्वारा "विश्व आदिवासी दिवस" के अवकाश को समाप्त कर दिया गया, जिससे आदिवासी समाज में रोष व्याप्त है। उन्होंने लिखा, 'मध्यप्रदेश सरकार ने वर्ष 2019 में "विश्व आदिवासी दिवस" को भव्यता एवं समारोहपूर्वक मनाया था तथा इस दिवस पर प्रदेश में मेरे द्वारा सार्वजनिक अवकाश भी घोषित किया गया था ताकि सभी वर्गों के लोग आदिवासी दिवस के आयोजनों में सम्मिलित हो सकें और इस दिवस को मनाने के उद्देश्य को पूर्ण करने में सहभागी बनें।

मुख्यमंत्री साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ ने प्रधानमंत्री मोदी के एक पेड़ मां के नाम के संकल्प को किया पूरा

(पेज 1 का शेष)

जीवों के जतन की जिम्मेदारी हम सबकी

धरती माँ का श्रृंगार हरियाली में निहित है। हमारी धरती को माँ के रूप में माना गया है और माटी को भी माँ का दर्जा दिया गया है। छत्तीसगढ़ को प्रकृति ने अनुपम सौगात दी है, जहाँ लगभग 44 प्रतिशत भू-भाग वनों से आच्छादित है। सरगुजा संभाग हरियाली का मुकुट धारण किए हुए है और बस्तर अंचल हरियाली के श्रृंगार से सजा हुआ है। यहाँ के मोहला और गरियाबंद के जंगल भी मन को मोह लेते हैं। इस समय प्रदेश में 'एक पेड़ माँ के नाम' अभियान के लिए वन विभाग सहित शासकीय, अशासकीय संस्थाओं और समितियों द्वारा पौधारोपण जोर-शोर से किया जा रहा है। धरती को उर्वरा, मौसम को खुशनुमा, स्वच्छ पर्यावरण, प्रदूषण रहित हवा, जलस्रोत को बढ़ावा और जल-जमीन-जंगल और जीवों के जतन की जिम्मेदारी हम सबकी सहभागिता से पूरी होगी। ग्लोबल वार्मिंग को रोकने और धरती को फिर से बेहतर बनाने के लिए हमें 'एक पेड़ माँ के नाम' अभियान में हिस्सेदारी करते हुए पौधे लगाना होगा।

पेड़-पौधों की महत्ता को समझ सकेगी

परिवार के हर सदस्य को एक पौधा रोपण करने की आवश्यकता है इनकी देखभाल छोटे बच्चों की तरह देखभाल करनी होगी। जब यह पौधा पेड़ बनेगा, तो यह प्राणवायु के साथ फल देगा, माँ के आँचल की तरह इसके पत्ते लह-लहाएँगे, पेड़ों में चिड़ियों का वास होगा और उनकी चह-चहाहट सुनने को मिलेगी। इससे वर्तमान और नई पीढ़ी पेड़-पौधों की महत्ता को समझ सकेगी।

महावृक्षारोपण अभियान- 2024 का शुभारंभ

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नवा रायपुर के अटल नगर स्थित जैव विविधता पार्क में 'एक पेड़ मां के नाम' महावृक्षारोपण अभियान-2024 का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री साय ने पूर्ण विधि विधान से पूजन कर पीपल के पौधे का रोपण कर महावृक्षारोपण अभियान की शुरुआत की। मुख्यमंत्री द्वारा अभियान का बैनर जारी किया गया। इस अभियान के तहत वन विभाग द्वारा प्रदेशभर में 4 करोड़ वृक्ष लगाये जा रहे हैं। इसी के अंतर्गत एक दिन में प्रदेश के 33 जिलों में कुल 4 लाख पेड़ लगाए गए। महावृक्षारोपण अभियान के शुभारंभ के मौके पर जैव विविधता पार्क में मुख्यमंत्री साय के साथ सभी कैबिनेट मंत्रीगणों, स्कूली बच्चों, सीआरपीएफ के जवानों, पुलिस और वन विभाग के अधिकारियों-कर्मचारियों ने 20 हजार पेड़ लगाए। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के 140 करोड़ लोगों से आह्वान किया है कि सभी अपनी मां के नाम से एक पेड़ लगाएं। उनके आह्वान पर यह एक आंदोलन बन गया है, हम लोग छत्तीसगढ़ में भी इसको अभियान के रूप में ले रहे हैं और अकेले वन विभाग का 4 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य है।

6 लाख पौधे वन विभाग ने लगाये

मुख्यमंत्री ने कहा कि आज प्रदेश के 33 जिलों में वन विभाग द्वारा 6 लाख पौधे लगाए जा रहे हैं। बहुत सी प्रजातियों के पेड़ लगाएं जा रहे हैं। पीपल का पेड़ जो 24 घंटा ऑक्सीजन देता है, नीम का पेड़, हर्रा बहेड़ा आंवला जैसे गुणकारी पौधे लगाए जा रहे हैं हर किसी को पेड़ लगाना बहुत आवश्यक है आप सब लोग देख रहे हैं कि पेड़ कम होने से गर्मी के दिनों में गर्मी बहुत बढ़ रही है इस साल तो रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पूरे देश में पड़ी है। पारा 50 डिग्री पहुंच गया। पूरे विश्व में गर्मी से मरने वालों की संख्या बहुत बढ़ गई है, ऐसे समय में बहुत आवश्यक हो जाता है कि हम सभी पेड़ लगाएं।

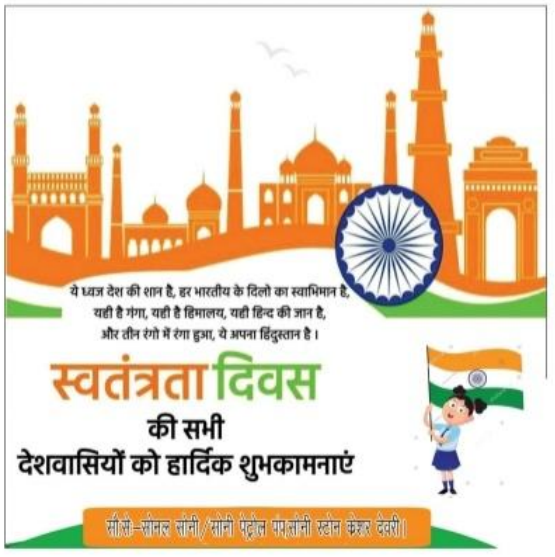

सम्पादकीय

बांग्लादेश में हो रही घटनाओं की आंच भारत पर भी पड़ी

बांग्लादेश में जो हो रहा है, उसे लेकर भारत की बड़ी आबादी चिंतित है। महिलाओं की राय उस चिंता को जाहिर तो कर ही रही थी, साथ में भारत सरकार को एक ऐसा सुझाव दे रही थी, जैसा सुझाव अब तक कम से खुले तौर पर कोई राजनीतिक दल नहीं दे पाया है। भारत की नीति रही है, किसी के आंतरिक मामले में दखल नहीं देंगे, साथ ही अपने आंतरिक मामले में किसी का हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं करेंगे। भारत ने संयमपूर्वक इसी नीति पर अब तक चलने का रिकॉर्ड बनाया है। लेकिन जिस तरह भारत के पड़ोस में हालात बदल रहे हैं, आए दिन अल्पसंख्यकों पर हमले हो रहे हैं, उसे देख भारत की आबादी का बड़ा हिस्सा अब मानने लगा है कि भारत को भी अपनी विदेश नीति बदलनी चाहिए और भारत को पहले की तुलना में संयम की बजाय चुनिंदा मुद्दों और मौकों पर गंभीर रूख अख्तियार करना चाहिए। उस संगठन की महिलाओं की राय तो इससे भी कहीं आगे की थी। उनका कहना था कि बांग्लादेश में भारत को सीधा हस्तक्षेप करना चाहिए। बांग्लादेश में जो हुआ, वह तो सबके सामने है। वहां के अल्पसंख्यक हिंदुओं को लगातार निशाना बनाया जा रहा है। इसे लेकर सीमा के इस पार चिंता होना स्वाभाविक है। आदिशक्ति की एक रूप ढाकेश्वरी देवी की आंचल में बसे ढाका शहर में हिंदुओं ने एकजुट होकर अपनी आवाज उठाई है, इसके बाद बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद युनूस हिंदू छात्रों के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात कर रहे हैं। वे बार-बार अल्पसंख्यकों की संपत्ति, घर आदि पर हमले को रोकने की अपील कर रहे हैं, इसके बावजूद बांग्लादेश के अल्पसंख्यक समुदाय को लेकर भारतीय आबादी का बड़ा हिस्सा चिंतामुक्त नहीं हो पाया है। हमले अब भी जारी हैं। कट्टरता की आड़ में सांप्रदायिक खटास ऐसी है कि खुलेआम हिंदू महिलाओं को अपमानित किया जा रहा है। एक महिला को भीड़ द्वारा अपमानित करने, उसे जबरिया तालाब में धकेलने, एक हिंदू व्यक्ति को तालाब में जाने के लिए मजबूर करने का बाद उस पर चौतरफा पत्थर का वार करने के दृश्य पूरी दुनिया ने देख लिया है। दिलचस्प यह है कि दुनियाभर में मानवाधिकार की ठेकेदारी करने वाले अमेरिकी और ब्रिटिश प्रभु वर्ग से ऐसी राय सामने नहीं आई है। हां, दुनिया भर में फैले हिंदुओं के संगठन लगातार बांग्लादेश में हो रहे अल्पसंख्यक अत्याचार पर ना सिर्फ सवाल उठा रहे हैं, बल्कि प्रदर्शन भी कर रहे हैं।

सवाल यह है कि क्या बांग्लादेश के हिंदुओं को निशाना इसलिए बनाया जा रहा है, क्योंकि वे शेख हसीना के समर्थक हैं। शेख हसीना का समर्थक होना एक कारण तो हो सकता है, लेकिन असलियत यह है कि बांग्लादेश में जिस तरह की ताकतें लगातार आगे बढ़ रही हैं, उनकी सोच के मूल में कट्टरपन है। बांग्लादेश के हिंदुओं को निशाना इसलिए भी बनाया जा रहा है, क्योंकि उन्हें बांग्लादेश की बहुसंख्यक मुस्लिम आबादी भारत समर्थक मानती है। तीन ओर से भारत से घिरे होने के बावजूद बांग्लादेश की बहुसंख्यक मुस्लिम आबादी भारत समर्थक तो कतई नहीं है। आज की बांग्लादेश की नई पीढ़ी इस अहसान के सोच से कोसों दूर है कि बांग्लादेश के जन्म ही नहीं, उसके निर्माण में भारत की बड़ी भूमिका रही है। उसे इतिहास से लेना-देना नहीं है, वह वर्तमान में खालिदा जिया के कट्टरपंथी राजनीतिक विचार और जमात ए इस्लामी के कट्टर विचार के प्रभाव में ज्यादा है। जिसके लिए उसकी कौम पहली प्राथमिकता है। बेशक इस्लाम के मूल में किसी धर्म की मुखालिफत का संदेश ना हो, लेकिन आधुनिक इस्लामी सोच के मूल में गैर मुसलमान से विरोध की सोच गहरे तक पैठ गई है। इसलिए भी भी बांग्लादेशी अपने ही पड़ोसी मुस्लिमों के निशाने पर हैं।

सियासी गहमागहमी

देशभक्ति के नाम पर शक्ति प्रदर्शन की क्या आवश्यकता?

पिछले दिनों राजधानी भोपाल में जिले के दो बड़े विधानसभा क्षेत्रों के विधायकों ने जबरदस्त शक्ति प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री से लेकर प्रदेश अध्यक्ष को खुश करने का काम किया। दरअसल तिरंगा यात्रा के नाम पर नरेला विधानसभा से विश्वास सारंग और हुजूर विधानसभा से रामेश्वर शर्मा ने तिरंगा यात्रा निकालने की घोषणा की। आलम यह हुआ कि तिरंगा यात्रा के दौरान दोनों ही राजनेताओं में शक्ति प्रदर्शन का एक दौर देखने को मिला। दोनों ने लंबी गाड़ियों की कतारें लगाई जिससे आमजन पूरी तरह से परेशान हुए और मुख्यमंत्री सहित प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा खुली जीप में खड़े होकर जनता का अभिवादन करते दिखाई दिए। माननीय को यह तक समझ नहीं आया कि उनकी इस बेहूदा शक्ति प्रदर्शन के कार्यक्रम से आमजन, बच्चे, बुजुर्ग और नौकरीपेशा कितने परेशान हुए। अगर माननीय विधायक जी को अगर शक्ति प्रदर्शन करना ही है तो आगे से वे ऐसे स्थान का चयन करें जहां आमजन को किसी प्रकार की परेशानी न हो। मेरी यही गुजारिश है प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से।

क्या शिवराज की छवि मन मस्तिष्क से हटा पायेंगे यादव?

पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान न सिर्फ प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर बल्कि राज्य में उन्होंने एक भाई और मामा के स्वरूप में 18 वर्षों तक राज किया है। सत्ता की शक्ति होने के बाद भी शिवराज सिंह चौहान के चेहरे पर कभी भी सत्ता का गुरुर नहीं दिखाई दिया और वह उसी मिलनसार भाव से आमजन से मिलते रहे जैसे वह पहले मिलते थे। चौहान के इस कार्यशैली को देख अब मोहन यादव भी आगे बढ़े रहे हैं। आमजन से मिलना, उनसे चर्चा करना, उनसे बातचीत करना यह सब यादव की दिनचर्या का हिस्सा बन गया है। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि यादव चाहते हैं कि वह प्रदेश की जनता के मन मस्तिष्क में बनी शिवराज सिंह चौहान की छवि को किसी तरह से बदल पायें लेकिन फिलहाल यह होता दिखाई नहीं दे रहा है। अब देखने वाली बात यह है कि डॉक्टर साहब आगे क्या-क्या पैंतरे अपनाते हैं।

हफ्ते का कार्टून

ट्वीट-ट्वीट

संविधान और आरक्षण व्यवस्था की हम हर कीमत पर रक्षा करेंगे। भाजपा की 'लेटरल एंट्री' जैसी साजिशों को हम हर हाल में नाकाम कर के दिखाएंगे।

मैं एक बार फिर कह रहा हूं - 50% आरक्षण सीमा को तोड़ कर हम जातिगत गिनती के आधार पर सामाजिक न्याय सुनिश्चित करेंगे।

जय हिन्द।

-राहुल गांधी

कांग्रेस नेता @RahulGandhi

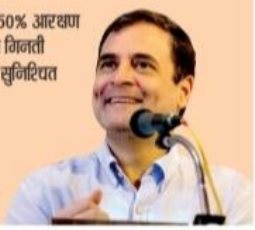

देश की सेवा करते हुए अपने प्राणों की आहुति देने वाले पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न श्री राजीव गांधी जी की जयंती पर मैं उन्हें नमन करता हूँ।

राजीव जी ने आधुनिक भारत के नव निर्माण की आधारशिला रखी थी। वे बीसवीं और इक्कीसवीं सदी को जोड़ने का महत्वपूर्ण कार्य कर रहे थे।

-कमलनाथ

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष

@OfficeOfKNath

राजवीरों की बात

बेबाकी से अपना पक्ष रखने वाली महुआ मोइत्रा भारतीय राजनीति का है मुखर चेहरा

समता पाठक/जगत प्रवाह

तृणमूल कांग्रेस की वरिष्ठ नेत्री महुआ मोइत्रा टीएमसी की मुखर नेता हैं। साथ ही वो पश्चिम बंगाल की कृष्णा नगर लोकसभा सीट से सांसद हैं। तेजतर्रार राजनीतिज्ञ, स्मार्ट, आकर्षक, भारतीय राजनीति में तेजी से लोकप्रिय हुआ एक चेहरा। लोकसभा में अपने भाषणों के लिए चर्चित. ऐसी नेता जो लगातार सरकार को कठघरे में खड़ी करने के लिए जानी जाती रही हैं। उनकी ये तब की तस्वीर हैं जब वो वर्ष 2019 के चुनावों में बंगाल के कृष्णानगर से अपने चुनाव अभियान में लगी हैं। यहां उन्होंने बीजेपी के उम्मीदवार को 16,000 से अधिक वोटों से हराया था। हालांकि उनका राजनीतिक करियर बहुत लंबा नहीं कहा जा सकता। वो अक्सर विवादों में रहती आई हैं। कभी बंगाल का स्थानीय मीडिया उनकी टिप्पणी से नाराज हो जाता है तो कभी बीजेपी से उनकी ठन जाती है तो कभी उन पर गलत तरीके से संसद में सवाल पूछने का आरोप लगता है। अब तो खैर वह संसद से निष्कासित ही हो चुकी हैं। महुआ पर कई बार विवादों के छींटे पड़े हैं। मोइत्रा का जन्म असम के कछार जिले के लाबाक में 12 अक्टूबर 1974 को हुआ था। वह एक बंगाली हिंदू ब्राह्मण परिवार से हैं। मोइत्रा ने कोलकाता के गोखले मेमोरियल गर्ल्स स्कूल से पढ़ाई की। उन्होंने 1998 में मैसाचुसेट्स, संयुक्त राज्य अमेरिका के माउंट होलोके कॉलेज साउथ हैडली से अर्थशास्त्र और गणित में स्नातक किया। मोइत्रा ने न्यूयॉर्क शहर और लंदन में जेपी मॉर्गन चेस के लिए एक निवेश बैंकर के रूप में काम किया। मोइत्रा को संसदीय भारतीय राजनीति में कदम रखे ज्यादा समय नहीं हुआ। पहले उन्होंने तृणमूल के टिकट पर करीमनगर से विधानसभा का चुनाव लड़ा और जीता, फिर वर्ष 2019 में उन्हें पार्टी ने लोकसभा का टिकट दे दिया। उन्होंने वर्ष 2008 में अपनी शानदार नौकरी छोड़ दी। वो भारत आ गईं। आते ही राहुल गांधी से मिलीं, उन्हें बंगाल में यूथ कांग्रेस में काम करने के लिए कहा गया। जल्दी ही वो बंगाल यूथ कांग्रेस में प्रमुख नेताओं में शामिल हो गईं। राहुल गांधी उन्हें जानते थे। उन पर विश्वास करते थे। उन्होंने बंगाल में बहुत अच्छी तरह कांग्रेस के कार्यक्रमों का संचालन किया था लेकिन जब कांग्रेस ने वहां चुनावों में लेफ्ट के साथ गठजोड़ किया तो वो क्षुब्ध हो गईं। तब उन्होंने तृणमूल कांग्रेस की ओर रुख किया।

तृणमूल में आने के बाद यहां भी उनका सिक्का चलने लगा। वो पार्टी की महासचिव बनीं। ममता दीदी के करीब आईं। उनका भरोसा जीता। जल्दी ही पार्टी ने उन्हें प्रवक्ता भी बना दिया। जब वर्ष 2016 में राज्य में चुनाव हुए तो उन्हें टिकट मिला। इसके बाद दीदी ने उनकी क्षमताओं पर भरोसा करते हुए उन्हें लोकसभा का टिकट दिया। अब वो लोकसभा में सबसे तेजतर्रार और प्रखर तरीके से मुद्दों को उठाने वाली नेता माने जाने लगी हैं। 2019 में उन्हें ममता बनर्जी ने लोकसभा चुनाव का टिकट दिया। ममता की उम्मीदों पर वो पूरी तरह खरी उतरीं और कृष्णा नगर सीट से सांसद बनीं। महुआ मोइत्रा 2019 के लोकसभा चुनाव में टीएमसी के टिकट पर कृष्णाणनगर सीट से मैदान में उतरीं और शानदार जीत दर्ज की। उन्होंसने भारतीय जनता पार्टी के कल्याण चौबे को करीब 64 हजार वोटों से हराया। 2016 में उन्होंने करीमपुर में विधानसभा चुनाव लड़ा और भाजपा के कल्याण चौबे को 16,000 वोटों के अंतर से हराकर जीत हासिल की। 2010 में वे 2010 में टीएमसी में शामिल हुईं।

क्या आप प्रकृति की संदेश सुन पा रहे हैं?

पर्यावरण की फिक्र

डॉ. प्रशांत सिन्हा

पर्यावरणविद्

जगत प्रवाह. भोपाल।

आज की तारीख़ में जब हम अपने घरों में सुरक्षित बैठे हैं, बाहर आसमान से लगातार बारिश की बौछारें धरती पर अपना प्रहार कर रही हैं। यह बारिश, जो कभी किसानों के लिए वरदान मानी जाती थी, अब अचानक से बाढ़ और तबाही का कारण बन गई है। भारत में कई दिनों से जारी मॉनसून की बारिश ने खूब कहर बरपाया। दिल्ली, हिमाचल, उत्तराखंड, पंजाब, मध्य प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा सहित दक्षिण भारत में भारी बारिश के "जल विस्फोट" ने जन जीवन पूरी तरह से प्रभावित किया। पहाड़ों में बारिश और लैंड स्लाइड से जान माल का काफी नुकसान हुआ। हिमाचल प्रदेश में सारी नदियां उफान पर हैं। उत्तराखंड में भी भारी बारिश से नदियों का जलस्तर बढ़ गया। इसके कारण कई जगहों पर बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। तेज बहाव के कारण सड़कें बहने से कई लोग फंस गए। जानकारी के अनुसार उत्तराखंड में अब तक 25 लोगों की मौत हुई है। केरल के वायनाड जिले के मुंडक्कई, चूरलमाला और मलप्पुरम जिले के नीलांबुर वन क्षेत्र में हुए भूस्खलन में कम से कम 178 लोग मारे गए जबकि 98 लोग लापता हैं। बिहार, असम, बंगाल, उत्तर प्रदेश, राजस्थान मध्य प्रदेश सहित कई राज्यों में बारिश ने कहर बरपाया है। क्या हमने कभी सोचा कि यह प्राकृतिक आपदा, जो हमारी जिंदगियों को हिला कर रख देती है, आखिर इसका असली कारण क्या है? क्या यह महज मौसम का बदलाव है या फिर यह हमारी धरती की पुकार है, जिसे हमने अनसुना कर दिया है? हमारे देश में कई इलाकों में भारी बारिश के कारण बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई है। नदियाँ उफान पर हैं, खेत खलिहान पानी में डूब चुके हैं, और गांव-शहरों के घर जलमग्न हो चुके हैं। यह दृश्य हृदय विदारक है और इससे न केवल मानव जीवन बल्कि पशु-पक्षियों और प्रकृति के अन्य जीवों पर भी गहरा प्रभाव पड़ता है। परंतु सवाल यह है कि क्या यह सब अचानक हो गया? या फिर हमने अपनी धरती के प्रति अपने दायित्व को भूलकर इसे अनदेखा कर दिया ? धरती मां, जो सदियों से हमारी जननी रही है, हमें पाल-पोस कर बड़ा किया, हमें अपने संसाधनों से सींचा, आज वह हमारी उपेक्षा से कराह रही है। हमने विकास के नाम पर जंगल काट दिए, नदियों को गंदा कर दिया, और प्रदूषण की मात्रा इतनी बढ़ा दी कि आसमान का रंग भी धुंधला पड़ गया। औद्योगिक विकास, शहरीकरण और अनियंत्रित जनसंख्या वृद्धि ने पर्यावरण पर ऐसा दबाव डाला कि धरती ने अपने स्वरूप को ही बदल दिया।

प्रकृति ने हमें हमेशा संकेत दिए हैं। बदलते मौसम, बेमौसम बारिश, असामान्य तापमान, ये सब धरती की ओर से चेतावनी थे कि अगर हमने अपने आचरण में बदलाव नहीं किया, तो परिणाम भयंकर होंगे। आज जब हम इस परिणाम का सामना कर रहे हैं, तो यह आवश्यक है कि हम धरती की पुकार को समझें और इस समस्या के समाधान की दिशा में कदम उठाएं।

भारी बारिश का प्रहार केवल जल भराव और बाढ़ तक ही सीमित नहीं है। यह हमारे कृषि क्षेत्र पर भी विनाशकारी प्रभाव डालती है। फसलें नष्ट हो जाती हैं, किसानों की मेहनत बर्बाद हो जाती है, और अंततः खाद्य संकट उत्पन्न होता है। साथ ही, बाढ़ के कारण पक्की सड़कों, पुलों, और इमारतों को भी नुकसान होता है, जिससे सरकार पर आर्थिक बोझ बढ़ता है। शहरों में जल भराव के कारण यातायात ठप हो जाता है, लोग अपने घरों में कैद हो जाते हैं, और जनजीवन अस्त-व्यस्त हो जाता है। बाढ़ के कारण जलजनित बीमारियों का खतरा भी बढ़ जाता है, जिससे स्वास्थ्य व्यवस्था पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है। यह स्थिति केवल वर्तमान समय तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसके दीर्घकालिक प्रभाव भी होते हैं, जिनका सामना हमें आने वाले समय में करना पड़ सकता है।

अब सवाल यह उठता है कि इस स्थिति के लिए कौन जिम्मेदार है? क्या यह केवल प्राकृतिक आपदा है, या फिर हमने अपनी गतिविधियों से इसे और विकराल बना दिया है? वैज्ञानिकों का कहना है कि जलवायु परिवर्तन एक प्रमुख कारण है। हमारे द्वारा उत्पन्न ग्रीनहाउस गैसें, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन, वायुमंडल में गर्मी को फंसा देती हैं, जिससे धरती का तापमान बढ़ता है। इस बढ़ते तापमान का सीधा असर मौसम के पैटर्न पर पड़ता है, जिसके परिणामस्वरूप अत्यधिक बारिश, सूखा और अन्य चरम मौसम की घटनाएं होती हैं। इसके अलावा, शहरीकरण के कारण नदियों और जलाशयों पर अतिक्रमण हुआ है। जहाँ पहले पानी का स्वाभाविक प्रवाह होता था, अब वहाँ कांक्रीट के जंगल उग आए हैं। इससे जल भराव की समस्या और गंभीर हो जाती है। जल निकासी व्यवस्था की कमी और जल प्रबंधन में लापरवाही ने भी स्थिति को और बिगाड़ दिया है।अब जब हम समस्या के कारणों को समझ चुके हैं, तो समाधान की दिशा में कदम उठाना अत्यंत आवश्यक है। सबसे पहले, हमें जलवायु परिवर्तन की समस्या से निपटने के लिए ठोस कदम उठाने होंगे। ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करना, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा देना और पर्यावरण की रक्षा के लिए कड़े कानून लागू करना इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम हो सकते हैं। इसके अलावा, जल प्रबंधन को सुधारने की आवश्यकता है। शहरों में जल निकासी व्यवस्था को मजबूत बनाना, नदियों और जलाशयों पर अतिक्रमण को रोकना और जल संरक्षण के उपायों को अपनाना आवश्यक है। हमें अपने जल स्रोतों का सतर्कता से उपयोग करना होगा और उन्हें संरक्षित करना होगा, ताकि भविष्य में ऐसी आपदाओं से बचा जा सके। शहरीकरण के कारण उत्पन्न हुई समस्याओं का समाधान भी हमें खोजने की जरूरत है। इसके लिए शहरों की योजना बनाते समय पर्यावरणीय पहलुओं का ध्यान रखना जरूरी है। प्राकृतिक जल मार्गों को बनाए रखना और हरे-भरे क्षेत्रों को संरक्षित करना महत्वपूर्ण होगा।

समाधान केवल सरकारी प्रयासों से नहीं आएगा। इसके लिए सामूहिक जागरूकता और प्रयास की आवश्यकता है। हमें अपनी जीवनशैली में बदलाव लाना होगा। छोटे-छोटे कदम, जैसे कि प्लास्टिक का कम उपयोग, बिजली और पानी की बचत और सार्वजनिक परिवहन का अधिक इस्तेमाल, बड़े बदलाव की दिशा में मददगार हो सकते हैं। स्कूलों और कॉलेजों में पर्यावरण शिक्षा को बढ़ावा देना भी महत्वपूर्ण है। आने वाली पीढ़ियों को पर्यावरण के प्रति जिम्मेदार बनाना और उन्हें जलवायु परिवर्तन के खतरों के प्रति सचेत करना आवश्यक है। इसके साथ ही, सामुदायिक स्तर पर वृक्षारोपण, जल संरक्षण और स्वच्छता अभियान चलाकर हम धरती के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभा सकते हैं।

पर्यावरण : संरक्षण और संवर्द्धन की आवश्यकता

आज की बात

प्रवीण कक्कड़

स्वतंत्र लेखक

जगत प्रवाह. भोपाल। पर्यावरण यानि ऐसा आवरण जो हमें चारों तरफ से ढंक कर रखता है, जो हमसे जुड़ा है और हम उससे जुड़े हैं और हम चाहें तो भी खुद को इससे अलग नहीं कर सकते हैं। प्रकृति और पर्यावरण एक दूसरे का अभिन्न हिस्सा हैं। कोई भी व्यक्ति या वस्तु चाहे वो सजीव हो या निर्जीव, पर्यावरण के अन्तर्गत ही आती है। पर्यावरण से हमें बहुत कुछ मिलता है, लेकिन बदले में हम क्या करते हैं? हम अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए इस पर्यावरण और इसकी अमूल्य संपदा का हनन करने पर तुले हैं। हमारे द्वारा कि गई हर अच्छी और बुरी गतिविधि का असर पर्यावरण पर पड़ता है। इस प्रकृति पर मानव ही सबसे अधिक बुद्धिशील प्राणी माना जाता है। अतः पर्यावरण के संरक्षण की जिम्मेदारी भी मनुष्य की ही है। आज हम पर्यावरण संरक्षण से जुड़े महत्वपूर्ण बिंदुओं पर प्रकाश डालकर समाज को इसके लिए जागृत करना चाहते हैं। पर्यावरण अर्थात् जिस वातावरण में हम रहते हैं। हमारे आस पास मौजूद हर एक चीज, जीव-जंतु, पक्षी, पेड़-पौधे, व्यक्ति इत्यादि सभी से मिलकर पर्यावरण की रचना होती है। हमारा इस पर्यावरण से घनिष्ठ संबंध है और हमेशा रहेगा। प्रकृति और पर्यावरण की अद्भुत सुंदरता देखते ही हृदय में खुशी और उत्साह का संचार होने लगता है। हरे भरे लहलहाते पेड़, आसमान में कलरव करते और चहचहाते पक्षी, जंगल में दौड़ते जीव जंतु, समन्दर में आती और जाती हुई लहरें, कल कल करके बहती हुई नदियां आदि जो मनोरम अहसास करवाते हैं, वो हमें अन्य कहीं से महसूस नहीं हो सकता। फिर भी ये अफसोस की बात है कि लोग आज भी इसके महत्व को समझ नहीं पाए हैं और इसे नुकसान पहुंचाते रहते हैं। वे यह नहीं जान पा रहे कि पर्यावरण की हानि करके वे अपने सर्वनाश को निमंत्रण दे रहे हैं।

जैसे-जैसे समय बीतता गया हमारी जरूरतें भी बढ़ती गई और इन जरूरतों को पूरा करने के लिए हम पर्यावरण के प्रति निर्दयता दिखाने लगे। हमने जनसंख्या वृद्धि पर पहले से रोक नहीं लगाई, जिससे लोगों को संसाधन कम पड़ने लगे और अत्यधिक रूप से पर्यावरण का विनाश होने लगा। गांवों से लोग शहरों की ओर पलायन करने लगे, पेड़ पौधों और वनों का विनाश होने लगा, जीव जंतुओं को अपने फायदे के लिए मारा जाने लगा, हर तरफ प्रदूषण फैल गया। जिससे पर्यावरण को बहुत नुकसान पहुंचा।

मध्यप्रदेश में भी पिछले कुछ वर्षों में पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने की दिशा में निरंतर कार्य हुए हैं। सिर्फ सरकार स्तर पर ही नहीं बल्कि सरकार के मंत्री और प्रभावशील लोगों ने भी अपने घरों, शासकीय बंगलों के बाहर लगे पेड़ों को कटवाकर वहां रेत और कंक्रीट का निर्माण करवा लिया गया। यह स्थिति तब है जब प्रदेश के मुख्यमंत्री खुद रोजाना एक पेड़ लगाते हैं और लोगों को पेड़ लगाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। उन्हीं के कैबिनेट मंत्री सहित अन्य प्रभावशील लोगों ने पेड़ों को क्षति पहुंचाने का काम किया है। अगर यह काम यही नहीं रूका तो आने वाले समय में पर्यावरण को इसी तरह से नुकसान होगा।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने किया 'स्वदेशी मेला' की विवरणिका का विमोचन

-संवाददाता

जगत प्रवाह. रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अपने निवास कार्यालय में छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों में भारतीय विपणन विकास केंद्र द्वारा आयोजित होने वाले 'स्वदेशी मेला' की विवरणिका का विमोचन किया। मुख्यमंत्री ने प्रतिनिधिमंडल को कार्यक्रम के आयोजन के लिए शुभकामनाएं भी दीं। बता दें कि प्रदर्शनी का आयोजन भारतीय विपणन विकास केंद्र (स्वदेशी जागरण फाउंडेशन की इकाई) द्वारा किया जाएगा। भारतीय विपणन विकास केंद्र के मेला प्रबंधक सुब्रत चाकी ने बताया कि पिछले दो दशक से यह कार्यक्रम प्रतिवर्ष विभिन्न जिलों में आयोजित किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि स्वदेशी मेला भारतीय उद्यमियों के लिए नए व्यावसायिक अवसर उपलब्ध करता है। यह मेला भारतीय उत्पादकों, ग्रामीण,

कुटीर, निजी, सहकारी और सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों के लिए लाभकारी व्यापार उपक्रम के रूप में उभरा है। जिससे इस कार्यक्रम की लोकप्रियता आमजन के बीच बढ़ती जा रही है। इस साल यह स्वदेशी मेला कबीरधाम में 17 से 23 अक्टूबर, बिलासपुर में 15 से 21 नवम्बर, रायपुर में 27 दिसम्बर 2024 से 3 जनवरी 2025, राजनांदगांव में 7 फ़रवरी से 13 फरवरी 2025 व जगदलपुर में 2 मार्च से 9 मार्च 2025 तक आयोजन किया जाएगा। इस अवसर पर डॉ. रामप्रताप सिंह, प्रान्त समन्वयक जगदीश पटेल, गोपाल कृष्ण अग्रवाल, प्रवीण मैशेरी, शीला शर्मा, युगबोध अग्रवाल, अमर बंसल, स्वदेशी मेला एवं भारतीय विपणन विकास केंद्र के प्रबंधक सुब्रत चाकी, अमरजीत सिंह छाबड़ा एवं अन्य स्वदेशी कार्यकर्ता उपस्थित थे।

(जगत फीचर्स)

भाजपा के सदस्यता अभियान– 2024 और कार्यशाला का शुभारंभ

राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह, सीएम साय समेत कई दिग्गज रहे मौजूद

-संवाददाता

जगत प्रवाह. रायपुर। प्रदेश भाजपा कार्यालय, कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में भारतीय जनता पार्टी के सदस्यता अभियान– 2024 और कार्यशाला का शुभारंभ राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह, क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल, प्रदेश संगठन महामंत्री पवन साय, प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव जी, केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू के साथ किया। इस दौरान उपमुख्यमंत्री अरुण साव, विजय शर्मा, सदस्यता अभियान के प्रदेश प्रभारी अनुराग सिंहदेव, मंत्री गण, सांसद गण, विधायक साथी, संगठन के वरिष्ठ पदाधिकारी एवं अन्य गणमान्य जन भी उपस्थित रहे।भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव ने कहा कि, भारतीय जनता पार्टी अपना सदस्यता अभियान संगठन के

पर्व के रूप में मनाएगी। सभी की नए सिरे से सदस्यता होगी। किरण सिंहदेव ने कहा कि 22, 23, 24 को जिलों में सदस्यता अभियान को लेकर कार्यशाला होगी। 26, 27, 28 को मंडल स्तर पर कार्यशाला होगी। प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव ने कहा कि विधायकों को 10 हजार, सांसदों को 20 हजार सदस्य, मेयर को पांच हजार सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा गया है। हर बूथ में दो सौ सदस्य बनाने का लक्ष्य तय किया गया है। वहीं, प्रदेश में 50 लाख सदस्य बनाने का लक्ष्य हमने बनाया है।बता दें कि इस बैठक में डिप्टी सीएम अरुण साव, विजय शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव, क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जमवाल विशेष रूप से मौजूद रहे। बता दें कि इस बैठक में सदस्यता अभियान की रूपरेखा पर चर्चा की गई। भाजपा के सभी मंत्री, सांसद, विधायक, प्रदेश पदाधिकारी, कोर ग्रुप के सदस्य व मोर्चा के पदाधिकारी मौजूद रहे।

कलेक्टर एवं जनप्रतिनिधियों ने बच्चों के साथ किया विशेष मध्यान भोजन

-नरेन्द्र दीक्षित

जगत प्रवाह. नर्मदापुरम। जिले में 78वें स्वतंत्रता दिवस समारोह उत्साह एवं उमंग के साथ मनाया गया। इस अवसर पर सीएम राईज स्कूल पवारखेडा के परिसर में स्थित माध्यमिक शाला में विशेष भोज का आयोजन किया गया। विशेष मध्यान भोजन कार्यक्रम में कलेक्टर सोनिया मीना एवं पुलिस अधीक्षक डॉ. गुरूकरण सिंह, विशेष अतिथि श्रीमती माया नारोलिया, नर्मदापुरम विधायक डॉ. सीतासरन शर्मा, नगरपालिका अध्यक्ष श्रीमती नीतू महेन्द्र यादव, जनपद अध्यक्ष भूपेन्द्र चौकसे, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी सौजान सिंह रावत, अपर कलेक्टर डी.के. सिंह, सिटी मजिस्ट्रेट असवन राम चिरावन, संयुक्त कलेक्टर अनिल जैन, एसडीएम नर्मदापुरम श्रीमती नीता कोरी सहित अधिकारियों ने बच्चों के साथ बैठकर मध्यान भोजन ग्रहण किया। मध्यान भोजन में सब्जी, पुरी, खीर एवं लड्डू का वितरण किया गया।माध्यमिक शाला स्कूल परिसर में कलेक्टर सोनिया मीना, राज्यसभा सांसद श्रीमती माया नारोलिया, जनपद अध्यक्ष भूपेन्द्र चौकसे एवं पुलिस अधीक्षक डॉ गुरुकरण सिंह ने विभिन्न प्रजाति के पौधों का रोपण किया।

प्रदेश छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री साय ने सपरिवार किया बाबा महाकाल के दर्शन

-दुर्गेश अरमोती

जगत प्रवाह, रायपुर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सावन के अंतिम सोमवार को उज्जैन के विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर पहुंचे। मुख्यमंत्री ने सपरिवार बाबा महाकाल के दर्शन किए। इसके बाद पूजा-अर्चना कर शिव जी का आशीर्वाद लिया। महाकालेश्वर मंदिर के पुजारियों ने पूजन संपन्न कराया। इस दौरान उनकी पत्नी कौशल्या साय और परिवार के लोग भी मौजूद रहे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव से मध्य प्रदेश के दौरे पर थे। महाकाल के दर्शन करने के बाद वह उज्जैन में प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से मुलाकात की। पूजन के पश्चात मुख्यमंत्री साय मंदिर परिसर स्थित श्री पंचायती महानिर्वाणी अखाड़ा पहुंचे। यहां पर उन्होंने आशीर्वाद लिया। अखाड़ा की ओर से मुख्यमंत्री साय व परिवार को प्रसाद भेंट किया गया। महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन के बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि आज श्रावण का आखरी दिन है। सोमवार है और रक्षा बंधन का पर्व भी है। सपरिवार बाबा महाकाल की शरण में आए हैं। भगवान का पूजन-अर्चन कर आशीर्वाद मांगा है कि छत्तीसगढ़ में खुशहाली हो, शांति हो, सुख-समृद्धि हो, सभी का जीवन मंगलमय और खुशमय हो। सभी लोग विकास की मुख्यधारा से जुड़े। आज रक्षाबंधन का पर्व भी है। सभी को शुभकामनाएं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय का सपरिवार उज्जैन पहुंचने पर प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने सर्किट हाउस पर उनका स्वागत किया। इस अवसर पर राज्यसभा सांसद बाल योगी उमेश नाथ महाराज, विधायक अनिल जैन कालूहेड़ा, विधायक सतीश मालवीय, संजय अग्रवाल एवं अन्य गणमान्य नागरिक मौजूद थे।

इंडियन मेडिकल एसोसिएशन हरदा द्वारा हड़ताल की घोषणा, ओपीडी और आईपीडी सेवाएं रहेंगी बंद

-प्रमोद बरसले

जगत प्रवाह, हरदा। हाल ही में कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में एक महिला डॉक्टर के साथ हुए भयावह बलात्कार और हत्या और उसके बाद राजनीतिक रूप से प्रेरित भीड़ की हिंसा के विरोध में एकजुटता दिखाते हुए, IMA नेशनल एवं स्टेट बॉडी के आवाहन पर हरदा जिले के सभी डॉक्टरों और चिकित्सा पेशेवरों ने सरकारी और निजी अस्पतालों में समस्त ओपीडी और आईपीडी सेवाओं को निलंबित करने का फैसला किया है। साथ ही डाक्टरों के अलावा शहर के अन्य गणमान्य नागरिकों से भी जुड़ने की अपील की गई है। इस विरोध प्रदर्शन का उद्देश्य पीड़ित के लिए त्वरित न्याय, देशभर में चिकित्सा पेशेवरों के लिए सख्त सुरक्षा उपाय और सुरक्षात्मक नीतियों के तत्काल कार्यान्वयन की मांग करना है।

मध्यप्रदेश शासन

देश की आज़ादी के लिए प्राणों की आहुति देने वाले वीर शहीदों को कृतज्ञतापूर्ण नमन

नरेन्द्र मोदी, प्रधानमंत्री

78 वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं

चौतरफा विकास का परचम लहराता मध्यप्रदेश

युवाओं के लिये गुणवत्तापूर्ण शिक्षा एवं व्यावसायिक क्षमता निर्माण के लिए सभी 55 जिलों में पी.एम. कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस प्रारंभ

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की पहल पर प्रदेश में पहली बार रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव हो रहे आयोजित

संबल योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, आहार अनुदान योजना एवं राशन आपके ग्राम जैसी योजनाओं के माध्यम से गरीब और जरूरतमंदों को सहायता

मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना में 1.29 करोड़ महिलाओं को रक्षाबंधन पर प्रतिमाह ₹1250 के अतिरिक्त ₹250 का विशेष उपहार, अब तक ₹22 हजार 924 करोड़ की सहायता, लाड़ली लक्ष्मी योजना के माध्यम से बेटियों की शिक्षा और स्वास्थ्य का ख्याल

मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना में 83 लाख से अधिक किसानों को ₹14254 करोड़ की सहायता

डॉ. मोहन यादव
मुख्यमंत्री

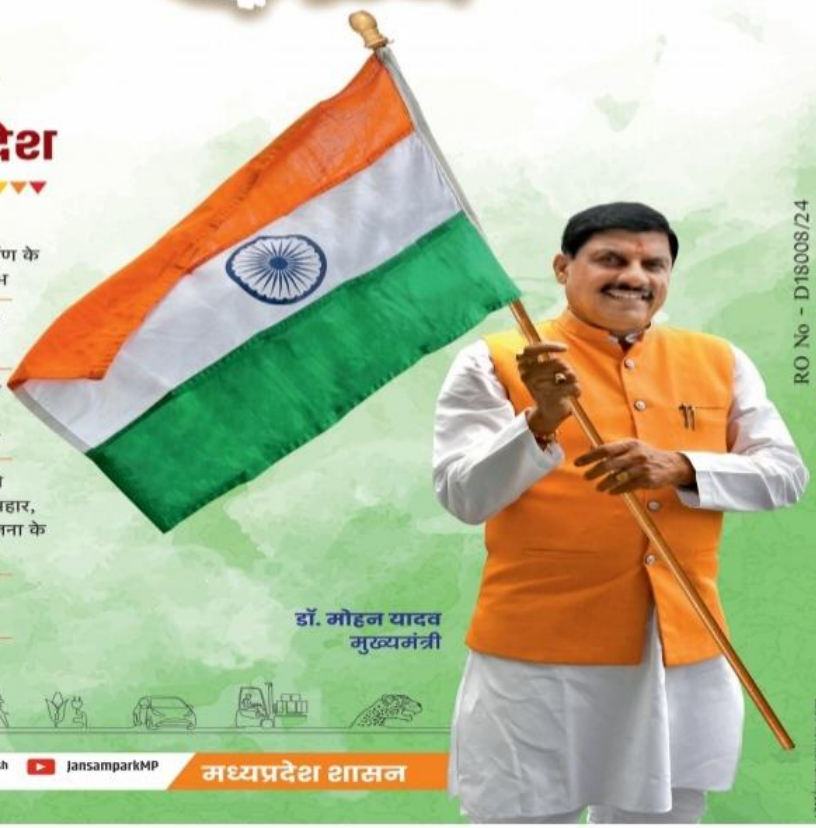

RO No - D18008/24

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से जुड़ने के लिए स्कैन करें

@Cmmadhyapradesh @jansampark.madhyapradesh
@Cmmadhyapradesh @jansamparkMP
JansamparkMP

मध्यप्रदेश शासन

मध्यप्रदेश जनसम्पर्क द्वारा जारी

स्वामी, प्रकाशक एवं मुद्रक विजया पाठक द्वारा जेयन आफसेट वर्क्स, पुल बोगदा भोपाल 462023 (मप्र) से मुद्रित तथा एफ-116/17, शिवाजी नगर, भोपाल (मप्र) से प्रकाशित। संपादक : विजया पाठक।
RNI-MPBIL/2011/39805 समाचार चयन के लिए पी.आर.बी. एट के तहत जिम्मेदार। (सभी विवादों का न्यायक्षेत्र भोपाल रहेगा।)